2017

एक दिवसीय कार्ययोजना के आधार पर तैयार

आदर्श ग्राम प्रारूप की आवश्यक कार्ययोजना

प्रो. गणेश कावडिया
प्रो. रेखा आचार्य

विकेंद्रित योजना पर राज्य योजना आयोग की पीठ
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

आदर्श ग्राम के मापदंडों की पहचान– (एक मॉडल गाँव)

कार्यशाला की अनुशंसा

आदर्श ग्राम के मापदंडों की पहचान– (एक मॉडल गाँव*)* पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राज्य योजना आयोग के सहयोग से अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 13 सितंबर 2017 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सरपंचो की क्षमता वर्धन करना तथा उन्हें उन सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है, जिनका लाभ लेकर वे अपने गाँवो को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सके।

मध्यप्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में अचंभित वृध्दि की एवं प्रदेश की वृध्दि दर लगभग 20 प्रतिशत औसतन रही है, इसके बावजूद गाँवों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं जैसे पानी, बिजली, रेल यातायात, सड़क परिवहन, अच्छी स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकी है। उच्च कृषि विकास भी गाँवो से पलायन को रोकने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। अतः आर्थिक विकास के मॉडल में ग्रामीण विकास को सर्वोपरी बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए गाँवो को आदर्शगाँव के रूप में विकसित कर आर्थिक विकास को समावेशी बनाया जा सकता है।

आदर्श ग्राम के माध्यम से सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों को एक छत के नीचें लाने का प्रयास है। प्रत्येक संसद सदस्य चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल का हो उसे गाँव गोद लेना होगा और उस गाँवों की आवश्यकता के अनुरूप कुछ मापदंड बनाकर उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। यह गाँव उसके चुनाव क्षेत्र (किंतु उसका पैतृक गाँव या ससुर के गाँव को छोडकर) का होना चाहिये।

विकास की इस कड़ी में सरपंच को अपने गाँव की अर्थव्यवस्था की संरचना को समझना होगा। एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा, जिससे गाँवों का सतत विकास संभव हो सके। उन्हें तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के बारे में जानना होगा जिससे वे इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से कर सके और आदर्श ग्राम के मापदंडो के अनुरूप अपने गॉव का विकास कर सके।

साहित्य संदर्भ में–

विभिन्न अध्ययनों से भी ये सिध्द हो गया है कि यदि कोई भी सांसद किसी गांव को गोद लेता हैं, तो वह उसमें काफी वक्त देगा। संबंधित गांव को आदर्श बनाने में जितना वक्त लगेगा, उतने वक्त में वह संबंधित गांव के हर व्यक्ति का चहेता बन जाएगा यानी जनता से सीधे संपर्क होने की वजह से उसका प्रेमभाव भी बढ़ेगा। जब किसी गांव से संबंधित जनप्रतिनिधि का आगाध प्रेम हो जाएगा तो वह उस गांव की समस्या को अनदेखी नहीं सकेगा **सिंह एस. (2015)**। इसी तरह भारत सरकार की रिपोर्ट की तर्ज पर **वी. के. (2017)** ने कहा है कि, कई राज्यों में राज्य सरकार आदर्श ग्राम योजना को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। जिससे गॉवो में सामाजिक विकास सूचकांक में सुधार भी हुआ है। इसी तरह आदर्श ग्राम योजना की सफलता के निष्कर्ष स्वरूप कहा है कि, यह योजना पूरे देश विशेषतः राजस्थान राज्य के परिदृश्य में निश्चित रुप से पूरी हो सकती है बशर्ते इसकों राष्ट्रीय व राज्य परिस्थितियों और शहर आधारित जरुरतों के अनुरुप लागू किया जाना चाहिए एवं इसके साथ ही भविष्य में विकास एवं प्रबंधों के लिए कुछ नमूने आदर्श सिद्ध करना होगा **अहमद एच. एवं मोदी आर.(2017)** । जबकि **नवभारत टाइम्स (2014)** के अनुसार आदर्श ग्राम योजना में मॉडल गॉव की अवधारणा में अवसंरचना को छोड़ दे तो सभी लक्ष्य पंचायत राज या अन्य ग्रामीण योजना से मेल खाती है। अगर एक गॉव भी मॉडल गॉव के रूप मे विकसित हुआ है तो उसका दायरा सीमित ही रह जाएगा एवं अन्य गॉवों के विकास को प्रेरित नही कर पाएगा। यह असंतुलन विकास की दुविधा है। इसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर सबसे बड़ी रूकावट यह कि इसके लिए अलग से धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि सांसदो से अपेक्षा की गई की वे अपनी संसदीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करे। साथ ही विकास से जुड़ी अन्य केंद्रीय योजनाओं तथा ग्राम पंचायतो को उपलब्ध कोष को समन्वित करना चाहिए **अनिल जैन (2018)**। वही **दीक्षित एच. एन. (2016)** ने भी ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजना का अध्ययन करते हुए, आदर्श ग्राम मॉडल का विवेचना की जिसमे पाया की योजना मे राज्य सरकारो का पूरा सहयोग एवं सभी विभागो में जरूरी तानमेल न होने के कारण योजना के लाभ संबंधित अच्छे परिणाम नहीं मिले है। अतः इनकी मूलभूत समस्या नीति निर्माण की है, इसे दूर करने के लिये केंद्र एवं राज्यों में गहन समन्वय करना आवश्यक है।

आदर्श ग्राम बनाने की कार्ययोजना–

सर्वप्रथम सरपंचो को अपनी ग्राम सभा में नियमित रूप से बैठक कर लोगों को सरकारी योजनाओं से परिचित करना होगा। लोगों की सहभागिता सुनिश्चत कर उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा।

- ❖ कुछ गाँवों का आर्थिक–सामाजिक संबंधो के आधार पर एक क्लस्टर बनाकर गाँवो को मजबूत बनाये एवं इनको एक इकाई मानकर विकास किया जाना चाहिये।
- ❖ गाँव में अग्रगामी (Forword Linkages) और पश्चगामी (Backword Linkages) संपर्कों के द्वारा संसाधनों की पहचान कर विकास करना होगा जैसे मेक्सिको ने किया।
- ❖ सभी सरपंचो को अपने गाँव के बारे में आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक जानकारी को सूचना पटल पर रखनी चाहिये।
- ❖ पंचायत के परिसंपत्ति रजिस्टर में बैंक बैलेंस व संपत्ति का लेखा जोखा स्पष्ट अंकित करे और अपने गाँव के पेडों की संख्या, चेक डेम, बावड़ी, तालाब इत्यादी का अंकेक्षर एवं गणना कर गाँव के संसाधनो की स्पष्ट जानकारी पंचायत में रखनी चाहिये।
- ❖ आदर्श ग्राम के लिए जल संरक्षण, वृक्षारोंपण, एवं पर्यावरण तथा वन्यजीवों के विकास की समुचित सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिये।
- ❖ गाँव में नये विकास कार्यों के साथ पुरानी परिसंपत्तियों का संरक्षण या मरम्मत भी नियमित तौर पर करवाया जाना चाहिये।
- ❖ गाँव का ऐसा मॉडल/परियोजना स्वयं तैयार करे, जिससे राजनेता, उद्योगपति तथा दानदाता राशि देने के लिए स्वेच्छा से विकास एवं धन की व्यवस्था कर गाँव के विकास में भागीदार बन सके।
- ❖ गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव मे ही रोजगार की संभावनाओ एवं अवसरों को तलाशने की आवश्यकता है। गाँव में ही उपलब्ध कच्चे माल आधारित कुटीर उद्योग स्थापित कर गाँव में रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- ❖ गाँवों में शिक्षा का विकास करने हेतू सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चत करना चाहिये। जिससे गाँव का हर व्यक्ति शिक्षित हो तथा इसमें कौशल विकास की शिक्षा भी दी जानी चाहिये ताकी वे पूर्णरूप से सक्षम एवं निपुर्ण बन

सके एवं विद्यालयों में शिक्षको की सही समय पर उपस्थिति के लिए गाँवों में बायोंमेट्रक मशीनें लगवायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

- ❖ कृषि आधारित उद्योग भी गाँवो में विकसित किये जाये तथा उनके द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद की पैंकेजिंग भी गाँव मे ही होनी चाहिये। स्वदेशी प्रौद्योगिकी एवं स्थानीय शोध से गाँवों को स्वावलंबन की ओर ले जाने का लक्ष्य रखना चाहिये। जिससे गाँव की अर्थव्यवस्था का विकास संभव होगा।
- ❖ सरकार के कार्यक्रम से गाँव के विकास को आधार बनाना चाहिये। ग्राम सभाओ द्वारा सरकारी योजनाओं में ग्रामीणो की सहभागिता को सुनिश्चत करना चाहिये।
- ❖ गाँव को आदर्श गाँव से Smart Village की ओर विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- ❖ गाँवों को खुले में शौच मुक्त कराने हेतू एक दल का गठन कर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा में कार्य किया जाना चाहिये।
- ❖ गाँव में सीसी नालियों के निर्माण की योजना बनायी जानी चाहिये।
- ❖ गाँवों को पक्की सडकों से जोड़ा जाना चाहिये।
- ❖ रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण तथा अधोसंरचना के विकास के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- ❖ स्थानीय नेतृत्व को सुदृढ़ तथा उनमें सशक्त इच्छा शक्ति को विकसित की जानी चाहिये। गाँव की पंचायत में हर समुदाय के व्यक्तियों को शामिल किया जाये और गाँव के समुदाय को सामूहिक रूप से मिलकर विकास करने की अवधारणा विकसित की जानी चाहिये।
- ❖ आदर्श ग्राम बनाने के लिए जरुरी है कि, गाँव की पहली पीढ़ी से लेकर आखरी पीढ़ी तक के लोगों को एक प्लेटफार्म पर आकर सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी सुनिश्चत की जानी चाहिये।
- ❖ गाँव में होने वाले बदलाव को एक मिशन के रूप मे देखा जाना चाहिये।

आदर्श ग्राम निर्माण मॉडल
(गाँवों का गॉव के लिये ग्रामवासीयों द्वारा)

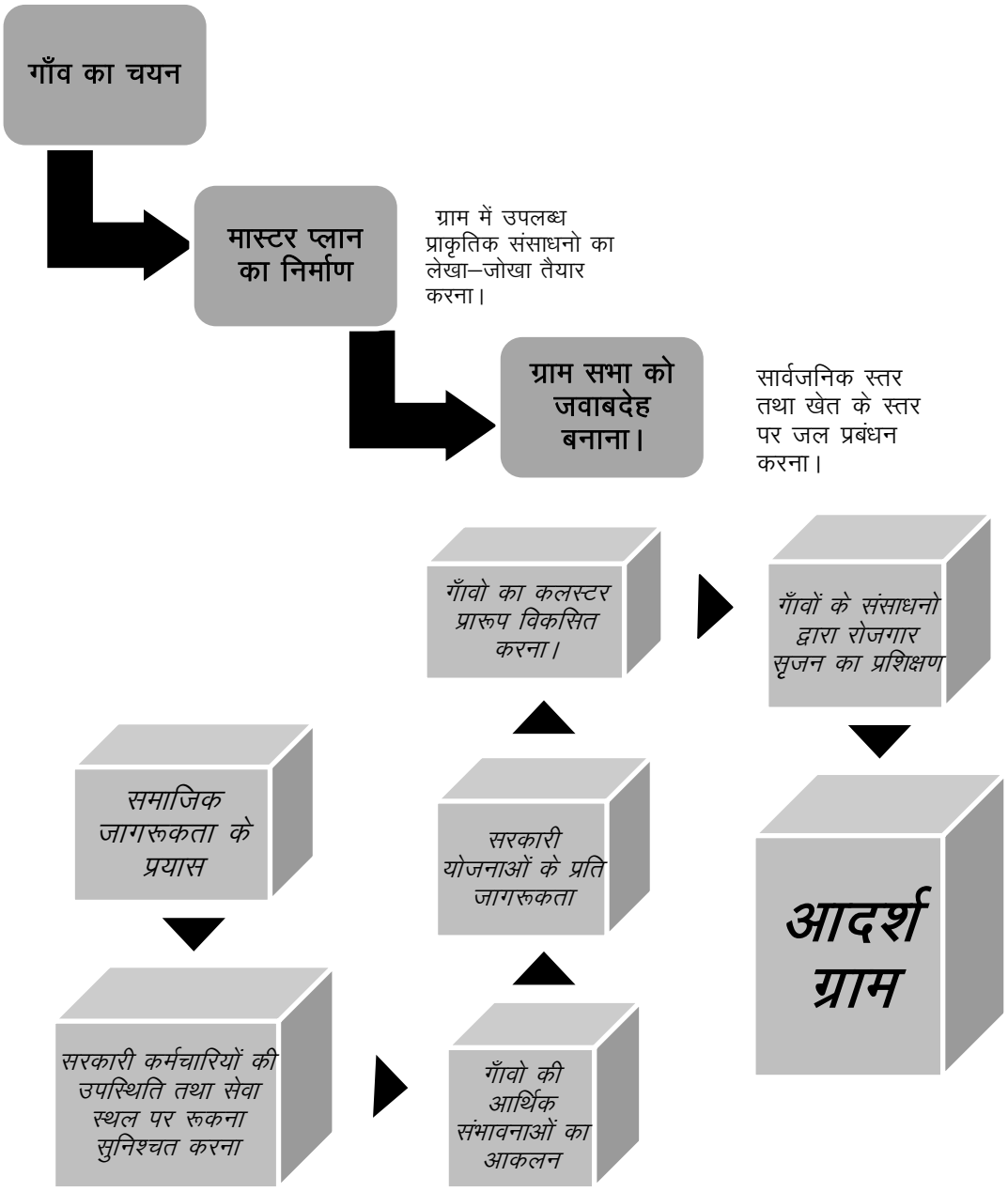

उपरोक्त आरेख द्वारा आदर्श ग्राम निर्माण मॉडल के स्वरूप के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। आदर्श ग्राम विशेष रूप से गाँवों का गॉव के लिये ग्रामवासीयों द्वारा बनाया गया प्रारूप है, अर्थात एक गॉव आदर्श गॉव के रूप में तभी तबदील हो सकेगा, जब गॉव के रहवासीयो में आपसी सहयोग के साथ जागरूकता बढ़ेगी। गॉव को आदर्श गॉव बनाने के लिये सर्वप्रथम किसी एक गॉव का चयन करना होगा, जिसे आदर्श गॉव बनाने का लक्ष्य

निर्धारित किया गया हो। इसके बाद गॉव का मास्टर प्लान बनाया जाये। जिसमें विशेष रूप से उस गॉव की ग्राम पंचायतो द्वारा गॉव मे उपलब्ध विभिन्न संसाधनो का लेखा जोखा तैयार करना होगा। चूकिं गॉव में अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन कृषि होता है, अतः ग्राम पंचायतो की जवाबदेही होगी की ऐसी योजना को बढ़ावा दे की खेत का पानी खेत में ही उपलब्ध हो जिससे खेतो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सके एवं गॉव का भूमी–जल के स्तर मे वृध्दि हो सके इस तरह की योजना का प्रशिक्षध के साथ उनको जागरूक भी करना होगा। गॉव को आदर्श ग्राम बनाने के लिये गॉव में बड़े स्तर पर गॉव के लोगों (रहवासीयो) में सामाजिक जागरूता को बढ़ावा देने के लिये लोगों में आपसी सहभागीता बढ़ानी होगी। गॉव में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति तथा उनको सेवा स्थल में रूकना सुनिश्चत करना होगा, इससे कर्मचारियों एवं लोगों के मध्य सीधे संपर्क स्थापित होगे। इस प्रकार कर्मचारियों को गॉव की समस्या की वास्तविक पहचान ज्ञात होगी एवं इससे समस्या का समाधान करना आसान हो सकेगा। पंचायतो द्वारा गॉव के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गॉव में ही आर्थिक संभावनाओं का आकलन करना होगा एवं गॉव के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनको जागरूक करना होगा जिससे योजनाओं का लाभ सही हितग्राहीयों को प्राप्त हो सके। गॉव के विकास हेतु गॉव का कलस्टर प्रारूप तैयार करना होगा। गॉव में बढ़ रहे रोजगार हेतू पलायन को रोकने के लिए गॉव में उपलब्ध संसाधनो द्वारा रोजगार का सृजन करना होगा एवं गॉव के लोगों की उत्पादकता क्षमता एवं कौशलता को बढ़ाने के लिये उनको प्रशिक्षित की व्यवस्था करना आवश्यक है। अतः इस प्रकार एक गॉव को आदर्श गॉव बनाया जा सकेगा।

मूल्यांकन–

मॉडल अनुसार प्रत्येक चरण पर गॉव के कार्यों की प्रगति अंको के आधार पर की जाये जिसमें प्रत्येक चरण को 5 अंक दिये जाये। जिसमें प्रथम चरण पूर्ण करने पर 1 तथा कार्य की प्रगति के आधार पर 2, 3 एवं 4 अंक तथा कार्य संपूर्ण होने पर 5 अंक प्रदान किये जाए। इस मॉडल आधार पर आदर्श ग्राम बनाने की संकल्पना न केवल मूर्त रूप लेगी बल्कि कार्य में लगने वाले समय एवं लागत की समीक्षा भी की जा सकेगी।

संदर्भ सूची–

जैन ए. (2018) सांसद आदर्श ग्राम योजना के रास्ते की बाधाएँ वेब दुनिया

अहमद एच. एवं मोदी आर.(2017) ग्रामीण विकास के मुद्दें एवं स्मार्ट गांवों की अवधारणा (राजस्थान के विशेष संदर्भ मे) VOL-1 P: ISSN NO.: 2394-0344

वी. के. (2017) सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गॉवों में उल्लेखनीय बदलाव. ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रकाशन 5633

दीक्षित एच. एन. (2016)गॉव के अधुरे सपने .दैनिक जागरण 5/8/2016

सिंह एस. (जून2015),सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव कुरूक्षेत्र पेज न. 17–20

https://navbharattimes.indiatimes.com/opinion/editorial/pm-satrted-ideal-village-scheme/articleshow/44791355.cms